भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या – *235

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन

***235. सुश्री कंगना रनौत:**

श्रीमती साजदा अहमद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है और ओडिशा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(घ) क्या आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): सरकार द्वारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

(ख): इस संबंध में यथासमय पर निर्णय लिया जाएगा।

(ग): केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/परिवार के पेंशनभोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36.57 लाख (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) और 33.91 लाख (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार) है। रक्षा कार्मिक और पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे।

(घ) और (ङ): आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा।

(च): विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डरों से इनपुट मांगे गये हैं। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।

*****